इकाई 12 भारतीय सीमाओं के बाहर ब्रिटिश प्रसार

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आप लोगों को भारत की सीमाओं से बाहर अंग्रेजी प्रसार के विषय में बताना है। उसके अंतर्गत औपनिवेशीकरण के प्रयासों और इसकी एक व्याख्या—यह कैसे और क्यों हुआ—को शामिल किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भारत से बाहर अंग्रेजी व्यापार और प्रसार के सामान्य कारणों पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- कैसे और कहां ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने प्रभाव का प्रसार किया इसकी खोज के बारे में बता सकेंगे; और
- उन क्षेत्रों की जानकारी दे सकेंगे जिन पर उन्होंने प्रत्यक्ष अधिकार नहीं किया फिर भी उनपर अपना पर्याप्त प्रभाव कायम रख सके।

12.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाइयों में आप साम्राज्यवाद की प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि शेष भारत को जीतने में अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल के संसाधनों का उपयोग किया और कैसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के मालिक धनी हो गये। इस इकाई से ऐसी आशा है कि आप इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हो जाएंगे कि उपनिवेशवाद का अपनी विशेषता के अनुरूप सतत् प्रसार होता रहा और एक उपनिवेश की सम्पदा का उपयोग दूसरे उपनिवेश पर प्रसार एवं नियंत्रण को सुदृढ़ीकरण करने में किया गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत के संसाधनों का उपयोग दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया की भूमि पर अपनी स्थिति के सुदृढ़ीकरण में किया। भारत को एक आधार के रूप में प्रयोग करते हुए, अंग्रेजों का नियंत्रण 1757-1857 के दौरान, दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मॉरीशस, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, दक्षिण पूर्व में अण्डमान और निकोबार, मलाया और फिलीपिन्स पर नियंत्रण स्थापित हो गया। केवल एशिया की मुख्य भूमि चीन, स्याम, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम को अपेक्षाकृत अछूता छोड़ा गया। परंतु इन क्षेत्रों को भी जैसा कि चीन के केस में हुआ, 1842 के बाद अंग्रेजी प्रभाव ने पर्याप्त मात्रा में जकड़ लिया।

इस प्रसार की कहानी भारत एवं चीन में ईस्ट इंडिया कम्पनी की समृद्धि तथा आकांक्षाओं के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसलिए कम्पनी के इतिहास के कुछ सुसंगत भागों का संक्षिप्त विवरण करना उपयोगी हो सकता है।

12.2 ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार

एक ही समय में भारत एवं चीन के साथ सक्रिय व्यापार बनाऐ रखना कम्पनी के लिए बड़ा उपयोगी रहा। भारतीय उत्पादों को चीन के बाजार में बेचे देते थे जिससे कम्पनी का लाभ और अधिक हो जाता। परंतु इससे उनको अन्य लाभ भी होते थे। इसलिए अब हम व्यापार की विस्तृत विवेचना करेंगे।

12.2.1 भारत के साथ व्यापार

आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लासी (1757) एवं बक्सर (1764) की लड़ाइयों के द्वारा किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से एशिया की मुख्य भूमि में प्रथम समृद्ध क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया।

1770 के दशक तक बंगाल को आर्थिक रूप से निचोड़ा जा चुका था और इसकी अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में हो गई। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनी के लाभ में कमी आयी और कम्पनी को व्यापक नुकसान होने लगा। इस प्रकार की हानि से दोहरी समस्याएं पैदा हुई क्योंकि न केवल इससे इंग्लैंड में रहने वाले कम्पनी के शेयर होल्डर्स के मुनाफे में कमी आयी बल्कि चीन के साथ भरपूर मुनाफे वाला व्यापार भी बरबाद होने लगा। चीनी, चाय, रेशम, रंगीन सूती वस्त्रों को यूरोप में ऊँचे मुनाफे से बेचा जाता था और इस व्यापर पर कम्पनी की इजारेदारी थी। परंतु इस समय चीनी लोग अपने सामान को चांदी के विनिमय के द्वारा ही बेचते थे और इस पर लगभग प्रतिवर्ष कई लाखों मूल्य की चांदी का खर्च आता था और 1767 से इस चाँदी का अधिकतर भाग बंगाल से प्राप्त होता था। इसलिए कम्पनी ने इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए ब्रिटिश संसद से कर्ज की मांग की। इसके बदले में संसद ने कम्पनी पर यह दबाव डाला कि इसका प्रशासन चलाने में संसद की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए और इसी कारण से 1772 के रेगूलेटिंग एक्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति काफी तीव्रता को प्राप्त कर रही थी और औद्योगिक हितों वाले लोग पूरब से कम्पनी की व्यापारिक इजारेदारी को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए भी दबाव डाला कि कम से कम कम्पनी जिस बाजार का धोबन कर रही है, उसी में ही कुछ हिस्सेदारी दी जाए। भारत में कम्पनी उसी समय भूमि पर अधिकार करने के लिए भारतीय राज्यों के साथ खर्चीले युद्धों को लड़ रही थी और धीरे-धीरे इसका वित्तीय आधार व्यापार एवं वाणिज्य से भू-राजस्व की ओर बढ़ रहा था अर्थात् व्यापारिक व्यवसाय से हटकर सरकार के व्यवसाय करना चाहती थी।

12.2.2 चीन के साथ व्यापार

जिस समय कम्पनी स्वयं को भारत में स्थापित कर रही थी उसी समय चीन के साथ इसके व्यापार में वृद्धि हो रही थी। भारत की तरह ही चीन के व्यापार पर भी कम्पनी की इजारेदारी थी।

चीन के साथ कम्पनी का प्रथम व्यापारिक संबंध 1701 में हुआ। आगामी पचास वर्षों में इसको रेशम, रंगीन सूती वस्त्रों, और चाय में मुनाफा होने लगा। परंतु कम्पनी के दृष्टिकोण से यहाँ पर निम्नलिखित ऐसी समस्या थी जिनका कम्पनी ने सामना किया :

- चीनी सरकार ने इसके व्यापार को कैन्टन के बंदरगाह तक सीमित करके इस पर कड़ा नियंत्रण लागू किया पर अधिकतर चीनी व्यापार चांदी के विनिमय के द्वारा होता था तथा उसमें भी चीनी सरकार के चांदी के डालर को ही प्राथमिकता प्रदान करती थी।

  1757 में बंगाल के कोष पर नियंत्रण स्थापित हो जाने से किसी सीमा तक इस समस्या का समाधान हो गया था। लेकिन 1769 के आते-आते बंगाल की समृद्धि काफी क्षीण हो चुकी थी। आगामी वर्षों में चीनी व्यापार की अदायगी के लिए निम्नलिखित कुछ प्रयत्नों के द्वारा कोशिश की गई —

- केन्द्रीय भारत के मालवा क्षेत्र में अफीम का उत्पादन करके चांदी को अलग करने का प्रयास किया गया, और
- दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्राप्त होने वाले मसालों को चीन एवं यूरोप में उच्च दामों पर बेचा गया।

12.2.3 प्रसार के सामान्य कारण

अंग्रेजों का भारत से बाहर प्रसार करना सम्भवतः दो कारणों से प्रभावित हो सकता है :

- **बाजार एवं आपूर्ति :** भारत में उत्पादित सामान के लिए नए बाजारों की खोज की आवश्यकता, चीन के साथ होने वाले व्यापार में विनिमय करने के लिए आपूर्ति और जो भी लाभ प्राप्त हो उससे दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेना को हथियारों से लैस करना तथा भोजन सामग्री की व्यवस्था करना।
- **लक्ष्य :** भारतीय साम्राज्य और चीन तथा भारत के साथ व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करने की आवश्यकता। इसके साथ-साथ दो सूक्ष्म कारणों को भी जोड़ा जा सकता है — प्रथम, ब्रिटिश विदेश नीति की यूरोप में बाध्यताएं और दूसरे, भारत में नौकरशाही के हित एवं नीतियाँ। यद्यपि इन कारणों का सापेक्ष महत्व एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न था और जैसा कि इस इकाई में आगामी विवेचन से स्पष्ट भी होगा।

बोध प्रश्न 1

1) ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत की सीमाओं से बाहर अपना प्रसार करने की क्यों आवश्यकता हुई? पचास शब्दों में अपना उत्तर दें।

....
....
....
....
....

2) चीन के व्यापार में बंगाल का क्यों महत्व था? पचास शब्दों में अपना उत्तर दें।

....
....
....
....
....

12.3 जलडमरूमध्य औपनिवेशिक बस्तियाँ

भारत से बाहर प्रथम अंग्रेजी औपनिवेशिक बस्तियाँ मलक्का के जलडमरूमध्य में थीं। उन्नसवीं सदी में इनको जलडमरूमध्य औपनिवेशिक बस्तियों के नाम से जाना जाता था।

12.3.1 पैनंग

मलक्का के जलडमरूमध्य के पैनंग प्रायद्वीप पर अंग्रेजों का प्रथम जहाज एडवर्ड बोनवेन्यर 1592 में पहुँचा। 1600 ई. के आते-आते मलाय के टापुओं में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किलेबन्दी की और बारह बस्तियों को स्थापित किया। 1625 के आसपास यह महसूस किया जाने लगा कि मलाय के मसालों से कम्पनी को कोई विशेष लाभ नहीं होता और तब अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भारत पर केन्द्रित करने का निर्णय किया गया। यद्यपि अंग्रेज व्यापारियों ने व्यक्तिगत स्तर पर इन उपनिवेशों के साथ निरंतर व्यापारिक संबंध बनाए रखे और अधिकतर टिन, हाथी दांत की चीजें तथा काली मिर्च का जलडमरूमध्य के उपनिवेशों से तथा सूती कपड़ों का भारत से व्यापार किया।

चीन के साथ कम्पनी के व्यापार में प्रसार हो जाने से पूर्वी समुद्र में एक ऐसे सुरक्षित बन्दरगाह की आवश्यकता महसूस की जानी लगी जहाँ पर चीन की यात्रा पर जाते समय एवं आते समय कम्पनी के सौदागर रूक सकें। 1782 में पूरब की ओर प्रसार करने पर उस वक्त गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाने लगा जबकि फ्रांसीसी एडमिरल डी सफरिन ने उत्तरी सुमात्रा में आखेहेज बन्दरगाह का प्रयोग करते हुए बंगाल की खाड़ी से अंग्रेजों की सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को बाहर कर दिया। जहाँ पर कम्पनी के जहाजों की मरम्मत की जा सकती थी वह केवल भारत के पश्चिमी तट पर बम्बई का बन्दरगाह था।

इसी कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से कार्य करते हुए 1784 में फ्रासिया लाइट ने पैनंग प्रायद्वीप में अंग्रेजी बस्ती बनाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये कैदाह के सुल्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में कम्पनी ने राजा की सैनिक सहायता करने का वायदा किया यदि उसके पड़ोसी उस पर आक्रमण करते हैं।

परन्तु मद्रास की सरकार ने इस समझौते का अनुमोदन कर देने से इंकार इस भय के कारण कर दिया कि पर्याप्त लाभ के बिना ही कम्पनी अनावश्यक युद्धों में सम्मिलित हो जाएगी। इस पर कैदाह के सुल्तान ने ताकत के बल पर पैनंग को वापस लेने का प्रयत्न किया। उसकी सेनाओं को फ्रासिया लाइट की सेनाओं ने पराजित कर दिया। 1791 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गये जिसके अनुसार पैनंग को अंग्रेजों को दे दिया गया तथा इसके बदले में कम्पनी को 6000 पौंड प्रति वर्ष सुल्तान को देने थे। 1800 ई. तक इस राशि की सीमा 10,000 पौंड कर दी गई और इसके बदले में कम्पनी को पैनंग के सम्मुख मलाय की मुख्य भूमि में एक पट्टा दे दिया गया। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर नौ सेना का अड्डा स्थापित करने में अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त कर ली। इससे लाभ यह हुआ कि विश्व की 60% काली मिर्च पैदा करने वाले सुमात्रा की काली मिर्च का व्यापार पैनंग के माध्यम से होने लगा।

मद्रास एवं बम्बई की भाँति पैनंग को भी 1805 में गवर्नर द्वारा शासित प्रेसीडैंसी बना दिया गया। पैनंग में स्थापित बस्तियों को बनाए रखने का खर्च बंगाल ने वहन किया और यहाँ पर कार्यरत 50 से अधिक ब्रिटिश अधिकारियों का

वेतन 42,000 पौंड प्रति वर्ष बंगाल के कोष से दिया जाता था। इन वर्षों में पैनंग के घाटे को पूरा करने के लिए 80,000 पौंड प्रति वर्ष बंगाल के द्वारा अदा किया गया।

12.3.2 सुमात्रा

इसी बीच 1783 में अंग्रेजों ने सुमात्रा में रिओ स्थित बुगी शासकों से भी सम्पर्क स्थापित कर लिया। बंगाल की कम्पनी सरकार ने सोचा कि यदि रिओ के साथ समझौता कर लिया जाए तब चीन को जाने वाला व्यापार मार्ग सुरक्षित हो जाएगा और रिओ द्वीप समूहों के व्यापार का आंतरिक बंदरगाह बन जाएगा। परंतु 1784 में डचों ने बुगियों पर आक्रमण कर दिया जिससे ईस्ट इंडिया कम्पनी को इस पर अपना विचार स्थगित करना पड़ा।

इसी समय पर यूरोप में घटित होने वाली घटनाओं ने भी हस्तक्षेप किया। 1787 में इंग्लैंड तथा प्रशा के संयुक्त हस्तक्षेप के कारण हालैण्ड की सरकार का तख्ता उलट दिया गया। इंग्लैण्ड ने नई सरकार से कहा कि वह श्रीलंका में ट्रिंकामाली तथा रिओं पर इंग्लैण्ड के नियंत्रण की स्वीकृति प्रदान करे और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कम्पनी हालैण्ड को भारत में वाणिज्य की कुछ सुविधाएँ प्रदान करेगी तथा वह सुमात्रा के पूरब में भी अंग्रेजी नौ सेना के कार्यवाहियों को भी बन्द कर देगी। परंतु डचों ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

इसी बीच फ्रांसीसी क्रांति घटित हो गई और फ्रांसीसी सेना ने 1794 में हालैण्ड पर अधिकार कर लिया। हालैण्ड की नई सरकार का इंग्लैण्ड के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया था। इंग्लैण्ड ने इसका बदला भारत में डच अधिकृत क्षेत्रों, श्रीलंका, सुमात्रा के पश्चिम तट, मोलूक्का, सुलावेशी में मेनदो, मलाक्का और रिओ को विजयी करके लिया।

डचों द्वारा अधिकृत जावा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि 1790 के दशक उत्तरार्द्ध में भारत का गवर्नर-जनरल वैलेजली था तथा उसने कम्पनी को भारत के अंदर ही खर्चीले युद्धों में संलग्न रखा और पश्चिम में मिस्र की ओर से फ्रांसीसियों ने भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। जिस समय डचों ने यूरोप में नैपोलियन के साथ गठबंधन कर लिया उसी समय कम्पनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अगस्त 1810 में गवर्नर-जनरल मिण्टो को आदेश दिया कि वह जावा से डचों को निष्कासित कर दे जिससे कि फ्रांस को दक्षिण-पूर्वी एशिया में दूसरा सैनिक अड्डा बनाने से रोका जा सके। भारत से सौ से अधिक जहाजों एवं 12000 सैनिकों का उपयोग जावा पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने के लिए किया गया।

1813 के बाद यूरोप में इंग्लैण्ड के डचों के साथ शांति एवं मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाने पर, दक्षिण-पूर्वी एशिया को विजयी करने के लिए पुनः आदेश दिए गए। सुरक्षा उद्देश्यों के कारण अंग्रेजों ने श्रीलंका एवं पैनंग पर अपने अधिकार को बनाए रखा। परंतु अब द्वीप समूहों में मसालों के उत्पाद की महत्वपूर्ण दो वस्तुओं लौंग एवं जायफल का उत्पादन मोलूक्का से बाहर भी होने लगा। मालवा के क्षेत्र में अफीम के उत्पादन ने चीनी व्यापार में अन्य वस्तुओं का स्थान तेजी से लेना प्रारम्भ कर दिया। इसी कारण से जलडमरूमध्य के उपनिवेशों को फिर से डचों को वापस कर दिया गया।

12.3.3 सिंगापुर

जावा पर अंग्रेजों के समय में जावा के लेफिट्नेंट गवर्नर स्टामफोर्ड टेफल्स ने अपना भय व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया को डचों के लिए छोड़ दिया गया तब वे सम्पूर्ण ब्रिटिश व्यापार को इस क्षेत्र से निष्कासित कर सकते हैं। उस समय के भारत के गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्स इससे सहमत था और उसने रेफल्स को आदेश भी दिया कि वह मलाया के द्वीप समूहों में एक उचित समझौता करने का प्रयास करे। जोहोर साम्राज्य की आंतरिक जटिल राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए रेफल्स एवं सिंगापुर प्रायद्वीप में अंग्रेज़ी फैक्ट्रियों को खोलने की फरवरी 1891 में सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर ली।

डचों ने सिंगापुर में अंग्रेजों की इस घुसपैठ का कड़ा विरोध किया और युद्ध की चेतावनी दी। कम्पनी के निदेशकों ने भी इस पर विचार किया और इसकी किलेबन्दी करने में रेफल्स को दोषी माना, लेकिन रेफल्स का समर्थन करने के लिए हेस्टिंग्स से कारण जानने की प्रतीक्षा की। परंतु इसका उत्तर तब स्पष्ट हो गया जब कम्पनी ने इस समझौते द्वारा प्रथम वर्ष में ही 3000,000 पौंड प्राप्त किए और 1825 तक प्रायद्वीपों के साथ होने वाले व्यापार में इसकी हिस्सेदारी दो-तिहाई हो गई। 1824 के आस-पास ब्रिटिश सरकार ने डचों पर दबाव डाला कि वे जोहोर के सुल्तान को (जो उस समय डचों के अधीन था) ब्रिटेन को सम्पूर्ण प्रायद्वीप देने के लिए कहें।

12.3.4 जलडमरूमध्य की औपनिवेशिक बस्तियाँ : सम्राट के उपनिवेश

अन्त में, 1867 में तीन बड़े प्रायद्वीप बंदरगाहों, जिनमें पैनंग, कलक्का, एवं सिंगापुर थे, को भारतीय प्रशासन से अलग कर दिया गया और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। उस समय जलडमरूमध्य में ब्रिटेन का प्रसार सुरक्षा उद्देश्यों एवं व्यापारिक कारणों से प्रभावित था। प्रसार के लिए भारत ने आदमियों एवं धन को उपलब्ध कराया। पैनंग के मामलें भारत ने व्यर्थ प्रशासन के लिए आर्थिक खर्च वहन किया परन्तु इससे प्राप्त होने वाला मुनाफा कम्पनी ने प्राप्त किया जैसे कि सिंगापुर उपनिवेशों से प्राप्त होने वाले मुनाफे को भारत नहीं लाया गया अपितु उसको इंग्लैण्ड ही ले जाया गया।

12.4 बर्मा

बर्मा के मामले में भी वाणिज्यिकी एवं सुरक्षा उद्देश्य एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे। बर्मा टीन, काली मिर्च और हाथी दाँत की वस्तुओं जैसी कुछ महंगी चीजों का निर्यात करता था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि बर्मा में इमारती लकड़ी की बहुतायत थी और कलकत्ता में स्थापित उद्योगों की मरम्मत तथा जहाज निर्माण के लिए लकड़ी की सप्लाई भी बर्मा से ही होती थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक इरावदी नदी का मुहावना दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा बंगाल बस्तियों को चावल की पूर्ति कराने वाला महत्वपूर्ण केन्द्र हो गया।

सर्वप्रथम 1753 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने निचले बर्मा के समुद्र तट पर नेगरायस में बस्तियों को स्थापित करने का प्रयास किया। 1758-59 में बर्मा के राजा आलोंगपाय ने कुछ सत्यता के साथ अंग्रेजों के द्वारा बर्मा के विद्रोहियों की सहायता करने का आरोप लगाया और 1759 में नेगरायस में जितने भी अंग्रेज थे उन सबकी हत्या कर दी गई। कम्पनी के निदेशकों ने अपनी ओर से इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की क्योंकि उन्होंने निर्णय किया कि नेगरायस इस सबका मूल्य चुकता करने में सक्षम न था। इस घटना के उपरान्त आगामी 20 वर्षों तक कम्पनी ने स्वयं को बर्मा से दूर ही रखा। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच इस दौरान बहुत ही कम सम्पर्क कायम रहा। बर्मा अपने एशियाई पड़ोसियों के प्रति निरंतर आक्रामक बना रहा। 1823-24 में, बर्मा की सेना विद्रोहियों का पीछा करती हुई असम तथा मणिपुर में प्रवेश कर गई तथा इन दोनों को अपने अधिकार में ले लिया और उन्होंने चिटगाँव पर आक्रमण करने की तैयारी की। परंतु असम, मणिपुर एवं चिटगाँव के इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सेना ने बर्मा की सेना पर आक्रमण किया और इसको प्रथम ऐंग्लो-बर्मा युद्ध (1824-26) के नाम से जाना जाता है।

12.4.1 प्रथम ऐंग्लो-बर्मा युद्ध

1824 में अंग्रेजों ने बर्मा पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल सेना की तीन बटालियनों ने उस समय विद्रोह कर दिया जिस समय उनको बर्मा के अराकन क्षेत्र के पड़ोस में चिटगाँव पर आक्रमण करने को कहा गया। मुख्य आक्रमण समुद्र से किया गया। बर्मा की सेनाएं आसानी से पराजित हो गई। राजा ने उस शांति संधि को स्वीकार कर लिया (24 फरवरी, 1926 की येनदाबो की संधि) जिसके अनुसार असम, मणिपुर, अराकन, तावाय और मेरगुई को अंग्रेजों के अधिकार में दे दिया गया। इस प्रकार राजा ने अपने अधिकतर समुद्र तट को खो दिया तथा उसके पास ऊपरी एवं केन्द्रीय बर्मा, पेगू और इरावदी के मुहाने वाले क्षेत्र शेष रहे। उसको अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजीडेंट (प्रतिनिधि) को रखने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा 1000,000 पौंड का हर्जाना अदा करना पड़ा।

इस युद्ध में अंग्रेज भारतीय सेना के 40,000 लोगों ने भाग लिया जिसमें से 15,000 लोग मारे गये। युद्ध का खर्च इतना अधिक था कि बर्मा युद्ध के दौरान अर्थात् 1824 से 1828 तक भारतीय बजट का घाटा 7,000,000 पौंड पहुंच गया।

6 एक भारतीय सिपाही

12.4.2 द्वितीय ऐंग्लो-बर्मा युद्ध

बर्मा राजधानी स्थित ब्रिटिश रेजीडेंट ने दावा किया कि बर्मा की सरकार उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती तथा 1839 में उसने बर्मा को छोड़ दिया। इसी बीच चीन के साथ व्यापार का प्रसार हुआ, दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों में भी काफी वृद्धि हुई और इसी कारणवश अंग्रेजी जहाजों की मरम्मत के लिए सरलता से उपलब्ध बर्मा की इमारती लकड़ी तथा अन्य उपनिवेशों में इरावदी नदी के मुहाने पर उत्पादित होने वाले चावल की आपूर्ति करने की भी आवश्यकता हुई। 1852 में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ने अंग्रेजों के सम्मान की पुनर्स्थापना का बहाना लेकर बर्मा पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय ऐंग्लो-बर्मा युद्ध 1852 में प्रारम्भ हुआ तथा अंग्रेजों ने 1853 तक पेगू और टोंगू के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बर्मा के राजा मिंदन मिन को अपनी राजधानी माण्डले में ले जाने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल की खाड़ी के संपूर्ण तट पर अधिकार हो गया। इस सदी के अन्त में, 1885 में, यह बहाना करके सम्पूर्ण बर्मा को अपने अधीन कर लिया कि राजा मिदन मिन एक दुराचारी राजा था तथा वियतनात स्थित फ्रांसीसियों के साथ मिलकर एशिया में अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए कार्य कर रहा था इस प्रकार बर्मा को भी ब्रिटिश भारत का एक प्रदेश बना दिया गया।

बोध प्रश्न 2

1) ऐंग्लो-बर्मा युद्धों पर पाँच पक्तियाँ लिखिए।

....

....

....

....

....

2) निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उन पर सही (√) या गलत (×) के चिन्ह लगाइए।

i) 1791 की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कैदाह के सुल्तान को 6000 पौंड प्रति वर्ष अदा किए।

ii) चीन के साथ अपने व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेज सुमात्रा के साथ एक समझौता करना चाहते थे।

iii) डचों को एक सबक सिखाने के लिए अंग्रेज जलडमरूमध्य में बस्तियों को स्थापित करना चाहते थे।

12.5 छोटे क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण

लघु बस्तियाँ या सापेक्ष रूप से छोटे उपनिवेश सुरक्षा के उद्देश्यों से कम महत्वपूर्ण थे और उनमें पड़ोसी बोरनियो और फिलीपीन्स, अण्डमान निकोबार प्रायद्वीप, श्रीलंका तथा मॉरीशस के क्षेत्र सम्मिलित थे। इन बस्तियों ने अन्य औपनिवेशिक शक्तियों जैसे कि हालैण्ड, स्पेन, फ्रांस और डेनमार्क का ध्यान भी आकर्षित किया। परन्तु हम केवल ब्रिटिश प्रयासों की ही चर्चा करेंगे।

12.5.1 बोरनियों एवं फिलीपीन्स

1701 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बोरनियों के दक्षिण तट पर मुख्य रूप से काली मिर्च के व्यापार के लिए बन्जेरमेशिन में एक किलेबन्द फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण वे शीघ्र ही अलोकप्रिय हो गये और 1707 में उनको निष्कासित कर दिया गया। 1756 में उस समय तक अंग्रेजी जहाजों का इसके साथ अनियमित सम्पर्क बना रहा जब तक कि डचों ने काली मिर्च के व्यापार पर अपनी इजारेदारी स्थापित करने में सफलता प्राप्त न कर ली।

इसके बाद बोरनियों में बसने का दूसरा प्रयास 1762 में उस समय किया गया जबकि यूरोप में सात वर्षों का युद्ध चल रहा था। 1762 में जिस समय स्पेन ने इंग्लैंड के ऊपर युद्ध की घोषणा की, उसी समय बंगाल से एक जहाजी बेड़ा स्पेन के उपनिवेश फिलीपीन्स को भेजा गया। इसने अक्तूबर 1762 में मनीला पर अधिकार कर लिया। मनीला में अंग्रेजों ने सुल्तान सुलू को स्वतंत्र करा दिया जिसको स्पेनियों ने कैद कर रखा था। सुल्तान ने उपहार स्वरूप प्रायद्वीप बालमबांगन अंग्रेजों को दे दिया। यह प्रायद्वीप बोरनियों से उत्तर की ओर था। स्पेन ने 1764 में पेरिस की संधि (1763 में लागू) के द्वारा मनीला को पुनः प्राप्त कर लिया। यह संधि सात वर्षीय युद्ध के समापन पर इस शर्त के साथ की गयी थी कि शाही फिलीपीन्स कम्पनी भारतीय सूती वस्त्रों को केवल अंग्रेजी सौदागरों से ही खरीदेगी।

बालम बांगन में निर्मित किले पर 1775 में स्थानीय लोगों के द्वारा हमला करके उसको नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ कम्पनी ने यह निश्चय किया कि बोरनियों एवं फिलीपीन्स इस योग्य न थे कि वहाँ पर पुनः बसने के लिए गंभीर प्रयास किये जाते। इसके बाद से इसका अधिकतर व्यापार केवल जलडमरूमध्य उपनिवेशों तक ही सीमित रह गया।

12.5.2 अंडमान तथा निकोबार प्रायद्वीप

हिन्द महासागर में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्य लघु उपनिवेशों में अंडमान एवं निकोबार प्रायद्वीप, श्रीलंका और मॉरीशस सम्मिलित थे। अंडमान व निकोबार प्रायद्वीप तथा श्रीलंका का अपना महत्व इस में निहित था कि ये दोनों चीन को जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षात्मक रूप से महत्वपूर्ण थे। 1789 में अंग्रेजों ने चीन के मार्ग पर जाने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रायद्वीप में पोर्ट ब्लेयर में बन्दरगाह की स्थापना की। परंतु जब कंपनी को पैनंग एवं ट्रिन्कोमाली प्राप्त हो गए, तब इसने 1796 में पोर्ट ब्लेयर को दण्डात्मक उपनिवेश के रूप में दोबारा स्थापित किया। 1756 में डेनमार्क ने निकोबार पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर नारियल, सुपारी का व्यापार करने तथा आरामगृह की स्थापना की। कम्पनी ने 1809 में डेनमार्क के आधिपत्य को उस समय समाप्त कर दिया जबकि उसने भारत में स्थापित अन्य डेन फैक्ट्रियों को प्राप्त कर लिया।

12.5.3 श्रीलंका

डच ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्रारम्भ में 17वीं शताब्दी में कोलम्बो को पूरब में डचों की शक्ति का केन्द्र बनाने की योजना बनायी। परन्तु 18वीं सदी में डचों ने स्वयं को जावा एवं श्रीलंका में स्थापित कर लिया तथा स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो गये। तभी अंग्रेजों ने भी निश्चय किया कि उनको भी श्रीलंका पर अधिकार करना चाहिए।

श्रीलंका के बन्दरगाह ट्रिन्कोमाली को हिंद महासागर के लंगर डालने वाले जहाजों के स्थल के रूप में 18वीं सदी में विकसित किया गया। इस पर बंगाल से चावल लाने वाले, मालद्वीप से कौड़ियां, मालाबार से सुपारी, मसाले, इलायची और काली मिर्च जिस पर डचों की इजारेदारी थी, वाले जहाज लंगर डालते थे।

1790 के युद्धों के समय डच सरकार फ्रांसीसी गठबंधन में थी जिससे अंग्रेजों ने डचों को श्रीलंका छोड़ने के लिए बाध्य किया। फरवरी 1796 में, श्रीलंका डचों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में आ गया और 1798 में

श्रीलंका को ताज उपनिवेश घोषित कर दिया गया अर्थात् जिसका तात्पर्य यह था कि एक ऐसा उपनिवेश जिसका प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाएगा न कि भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा।

12.5.4 मॉरीशस

श्रीलंका की ही भाँति मॉरीशस आर्थिक रूप में कम महत्ववाला उपनिवेश था और यह भारत से दक्षिण-पश्चिम की ओर हिंद महासागर में स्थित था। 1721 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस पर अधिकार कर लिया और इसका नाम इले-दी-फ्रांस रख दिया। इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी के जहाजों पर आक्रमण करने के लिए विकसित किया गया। द्वितीय तथा तृतीय ऐंग्लो-फ्रेंच युद्धों के समय फ्रांसीसी जहाज मद्रास तथा कोरीमण्डल तटों पर ब्रिटेन के जहाजों पर आक्रमण करने के लिए इस बन्दरगाह पर आए थे।

1810 में भारत के गवर्नर-जनरल मिण्टो ने मॉरीशस से फ्रांसीसियों को निकालने के लिए एक अभियान को संगठित किया। इले-दी-फ्रांस पर अधिकार करने के बाद इसका पुनः डच नाम मॉरीशस रख दिया गया और पड़ोस के स्थल इले-दी-बोबों का नाम रियूनियन कर दिया गया। फिर भी कम्पनी ने इस प्रायद्वीप के प्रशासन को अपने हाथों में नहीं लिया और इसको ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया तथा यह ताज उपनिवेश बन गया।

12.6 नेपाल

दक्षिण एशिया में इस काल में अंग्रेजों का मुख्य भूमि पर भारत से बाहर होने वाला प्रसार केवल नेपाल एवं अफगानिस्तान तक ही सीमित था।

ईस्ट इंडिया कंपनी का नेपाल में प्रथम हस्तक्षेप 1767 में उस समय हुआ जब कि कम्पनी की कौंसिल ने कलकत्ता में पटना नेपाल घाटी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। घाटी में पहले से ही कुछ अव्यवस्था फैली थी। गोरखा सरदार राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का राजा बनने की इच्छा से नेपाल पर आक्रमण किया। इससे पटना और नेपाल के बीच होने वाले व्यापार में विघ्न पड़ा और इसलिए कम्पनी ने पटना स्थित कैप्टन किनलोक को पृथ्वी नारायण शाह पर आक्रमण करने का आदेश दिया। परन्तु गोरखों ने आक्रमण को रोक दिया।

आगामी वर्षों में गोरखों ने नेपाल के मल्ल शासकों को पराजित कर दिया और पृथ्वी नारायण शाह नेपाल का राजा हो गया। उसके उत्तराधिकारियों 1792 में पटना में ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ एक सुदृढ़ व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए।

शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों को दक्षिण एशिया की एक निर्णायक शक्ति के रूप में माना जाने लगा। गवर्नर-जनरल वेलेजली ने भारत में कम्पनी का क्षेत्रीय प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए सहायक संधियों की व्यवस्थाओं का प्रचलन किया। इसी समय 1801 में अंग्रेजों ने नेपाल के साथ संधि करने का प्रयास किया (संधि पर अक्तूबर 1801 में हस्ताक्षर हुए) और इस संधि के अनुसार नेपाल सरकार ने ब्रिटिश रेजीडेन्ट को काठमाँडू में रखने की सहमति प्रदान कर दी। रेजीडेन्ट के पास पहले से ही ये आदेश थे कि वह नेपाल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करे तथा विशेषकर तिब्बत से सोने की आपूर्ति एवं नेपाल के जंगलों से प्राप्त होने वाली समृद्ध इमारती लकड़ी एवं देवदार का पता लगाए। परंतु नेपाल के साथ शत्रुता के कारण अंग्रेज रेजीडेन्ट को मार्च 1803 में भारत वापस बुला लिया गया। भारत के साथ लगी 1,100 किलोमीटर लम्बी सीमा पर कुछ गाँवों पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहुत सी समस्याएं पैदा होती रहीं।

गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स के समय में अक्तूबर 1814 में नेपाल एवं अंगरेजों के बीच युद्ध हुआ। कम्पनी की सेना का नेतृत्व मार्ले, ओश्तेर लोनी, वूड एवं कर्नल निकोल्स के द्वारा नेपाली सेना पर एक कड़ा हमला इस आशा के साथ किया गया कि वे सम्पूर्ण सीमा पर उनका सामना करेगी। परंतु उन्होंने पहाड़ के लोगों के संघर्ष करने की क्षमता को कम करके आंका था। नेपाल को पराजित करने में एक वर्ष से अधिक का समय लग गया तथा सगौल की संधि (दिसंबर 1815) के द्वारा नेपाल सतलुज की पहाड़ियों, गढ़वाल और कुमायूँ के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हो गया तथा पुनः एक अंग्रेज को रेजीडेन्ट के रूप में रखने के लिए भी तैयार हो गया।

तराई के समृद्ध क्षेत्रों को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि नेपाल की अधिक भूमि को प्राप्त करने से अब कोई विशेष आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वे नेपाल के मामलों में कम रुचि लेने लगे।

12.7 अफगानिस्तान

1830 के आस-पास कम्पनी के अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अफगानिस्तान पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने के स्थान पर उसका नेपोलियन के फ्रांस तथा रूस के जार से भारत की सुरक्षा के लिए एक मध्यवर्ती राज्य के (buffer) रूप में उपयोग किया जाए। 1836 में अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने की पेशकश की और इसके बदले में उसने यह आशा की कि जिस पेशावर घाटी को पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान से ले लिया था उसे पुनः अफगानिस्तान को वापस कर दिया जाएगा। परंतु गवर्नर-जनरल ऑकलैंड

ने रणजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्र को देने से इंकार कर दिया तथा अफगानिस्तान के रूस, फ्रांस या टर्की के साथ गठबंधन का विरोध किया। दोस्त मोहम्मद ने रूस के साथ मित्रता करने की उत्सुकता दिखायी।

इस स्थिति में ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को बल प्रयोग करके सत्ता से हटाने की योजना बनायी। कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस योजना पर अपनी सहमति दे दी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 26 जून 1838 को त्रिपक्षीय संधि अफगानिस्तान के पुराने शासक शाह शुजा, रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच सम्पन्न हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों, रणजीत सिंह तथा शाह शुजा तीनों की संयुक्त सेना काबुल पर आक्रमण करने के लिए दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने के लिए एकत्रित हुई।

"सिंधु की सेना" के नाम से पुकारे जाने वाली इस सेना ने अप्रैल 1839 में कंधार पर अधिकार कर लिया, तथा गजनी पर जुलाई में। इन पराजयों से दोस्त मोहम्मद इतना निराश हुआ कि उसने सिंहासन का परित्याग कर दिया और वह काबुल के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक नगर बेमिया को भाग गया। शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया गया। ब्रिटिश सेनाओं ने भारत वापस लौटने के स्थान पर काबुल, कन्धार, जलालाबाद तथा गजनी में छावनियां बना लीं। इसी बीच दोस्त मोहम्मद को सितम्बर 1840 में खोलूम के वली से सैनिक सहायता प्राप्त हो गई। उसने दिसम्बर में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया परंतु वह असफल रहा। उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया। तथा नवम्बर में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया।

1841 के बसन्त में अंग्रेजों के विरुद्ध लोकप्रिय असन्तोष शुरू हुआ। सितम्बर 1841 में कई जगहों पर जन विद्रोह फूट पड़े। काबुल में अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी गई और उनकी सैनिक छावनियों पर कब्जा कर लिया गया। इसी प्रकार की घटना गजनी कंधार तथा जलालाबाद में हुई और कोहिस्तान की संपूर्ण गोरखा सेना को मार डाला गया। अंततः दिसम्बर 1841 में अंग्रेजों ने तीन दिन के अंदर अफगानिस्तान को खाली करने की अपमानजनक शर्त को स्वीकार किया। वापस लौटती सेनाओं पर भी बर्फीली दर्रों पर हमला किया गया और काफी बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना को मार डाला गया।

मई 1842 में अंग्रेज सेना पुनः संगठित हो गई और उसने कंधार तथा जलालाबाद को अपने अधीन कर लिया। भारत से सेना के पहुँचने पर सितम्बर 1842 में काबुल पर भी अधिकार कर लिया गया। इस विजय की अंग्रेजी सेना को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। काफी मात्रा में आदमियों तथा धन की कुर्बानी से अफगान युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सेना अजेय नहीं थी और उसको अफगान पर्वत आदिवासियों जैसी युद्ध नीतियों को अपनाकर पराजित किया जा सकता था। इसके बाद अंग्रेजों ने स्वयं को उत्तर-पश्चिम सीमाओं तक सीमित कर लिया तथा सैन्य बल के आधार पर अफगानिस्तान में प्रवेश करने का फिर कभी साहस न किया।

बोध प्रश्न 3

1) बर्मा में अंग्रेजों की क्यों रुचि थी? 250 शब्दों में उत्तर दें।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

2) कंपनी के अधिकारियों ने किस प्रकार से अफगान युद्ध को न्यायोचित बताया? पाँच पंक्तियों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

3) नेपाल में अंग्रेजों की रुचि क्यों समाप्त हो गई? पाँच पंक्तियों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

12.8 सारांश

इस इकाई में हमने देखा कि अंग्रेजों ने फिलीपीन्स जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने और अपने व्यापार का प्रसार करने के लिए भारतीय सीमाओं से बाहर के क्षेत्रों में रुचि दिखायी। मॉरीशस तथा श्रीलंका जैसे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अंग्रेजों ने अपने भारतीय साम्राज्य तथा व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया। कुछ अवसरों पर, उदाहरणार्थ नेपाल एवं अफगानिस्तान के मामले में, अंग्रेजों ने स्वयं को दुस्साहसिक कूटनीति एवं युद्ध में उलझाया। इन सभी गतिविधियों पर भारतीय कोष से पैसा खर्च किया गया और भारतीय सिपाहियों ने आवश्यक सुरक्षा चक्र को उपलब्ध कराया। भारत की कीमत पर ही इंग्लैण्ड सम्पूर्ण दक्षिण एशिया तथा हिन्द महासागर की एशियाई भूमि पर एक शक्ति बन सका।

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) उप-भाग 12.2.3 देखें।
2) उप-भाग 12.2.1 देखें।

बोध प्रश्न 2

1) उप-भाग 12.4.1 एवं 12.4.2 देखें।
2) i) √ ii) √ iii) ×

बोध प्रश्न 3

1) देखें भाग 12.4
2) देखें भाग 12.7
3) देखें भाग 12.6

मानचित्र 3 भारत और पड़ोसी देश